



The Himachal Pradesh Medicare Service Persons and Medicare Service
Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Amendment
Act, 2017

Act 9 of 2017

Keyword(s):

Medicare Service Persons, Medicare Service Institutions, Violence, Damage,
Property

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 5 जून, 2017

संख्या: एल0एल0आर0-डी0(6)-5/2017-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 01-06-2017 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा-संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) संशोधन विधेयक, 2017 (2017 का विधेयक संख्यांक 4) को वर्ष 2017 के अधिनियम संख्यांक 9 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश ई-राजपत्र में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,
(डा0 बलदेव सिंह),
प्रधान सचिव (विधि)।

2017 का अधिनियम संख्यांक 9

हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा-संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) संशोधन अधिनियम, 2017

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 1 जून, 2017 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा-संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) अधिनियम, 2009 (2010 का अधिनियम संख्यांक 5) का संशोधन करने के लिए **अधिनियम** ।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम.—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा- व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा-संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) संशोधन अधिनियम, 2017 है।

2. धारा 3 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश चिकित्सीय सेवा-व्यक्ति तथा चिकित्सीय सेवा-संस्था (हिंसा और सम्पत्ति के नुकसान का निवारण) अधिनियम, 2009 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) में, "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

3. धारा 4 का प्रतिस्थापन.—मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"4. अपराध का संज्ञान.—(1) इस धारा के अधीन किया गया अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा।

(2) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा लिखित में की गई शिकायत के सिवाय न करेगा।"

THE HIMACHAL PRADESH MEDICARE SERVICE PERSONS AND MEDICARE SERVICE INSTITUTIONS (PREVENTION OF VIOLENCE AND DAMAGE TO PROPERTY) AMENDMENT ACT, 2017

(As Assented to by the Governor on 1ST JUNE, 2017)

AN

ACT

to amend the Himachal Pradesh Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Act, 2009 (Act No. 5 of 2010).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Amendment Act, 2017.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Medicare Service Persons and Medicare Service Institutions (Prevention of Violence and Damage to Property) Act, 2009 (hereinafter referred to as the “principal Act”), in sub-section (1), for the words “one year”, the words “three years” shall be substituted.

3. Substitution of section 4.—For section 4 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :—

“4. Cognizance of offence.— (1) Any offence committed under this Act shall be cognizable and non-bailable.

(2) No court shall take cognizance of an offence punishable under this Act except upon a complaint in writing made by the officer authorized by the Government, by notification, in this behalf.”.